ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

11 अप्रैल, 2018 • वर्ष 1, अंक 12

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में लखनऊ में आहूत बैठक में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अन्य मंत्रिगणों के साथ

- किसानों के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना
- अपराधियों में जगा पुलिस का खौफ
- निजी स्कूलों की मनमानी रोकेगा फीस नियंत्रण कानून
- गंगा के किनारों पर फैलेगी हरियाली
- यूपी में निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण शुरू
- फिर से चलेगी पीलीभीत की मझोला सहकारी चीनी मिल

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

14 अप्रैल
से 5 मई तक मिलेगे विद्युत कनेक्शन

एपीएल
परिवारों को 50 रूपये की 10 किश्तों पर कनेक्शन

नि:शुल्क
कनेक्शन मिलेंगे बीपीएल परिवारों को

अनुसूचित
जाति/जनजाति तथा दलित बहुल ग्रामों में चलेगा अभियान

3387 दलित बहुल गांवों में मिलेंगे बिजली कनेक्शन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलितों के कल्याण के लिये निरन्तर कार्यरत रहती है। प्रदेश में ऐसे कई दलित बहुल गांव हैं, जहां परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए बाबा साहेब डा. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल से ग्राम स्वराज अभियान में सौभाग्य योजना के तहत प्रदेशभर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल 3387 गांवों में विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। यह अभियान 5 मई तक चलेगा।

अभियान की प्रगति रिपोर्ट होगी वेबसाइट पर अपलोड

अभियान की प्रतिदिन की रिपोर्ट सौभाग्य पोर्टल पर भी अपलोड की जाए। अभियान के तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के 19 जिलों के 1425 गांवों का चयन किया गया है।

किश्तों पर मिलेगा कनेक्शन

योजना के अंतर्गत लाभार्थी बीपीएल परिवारों को मुफ्त और एपीएल परिवारों को 50 रूपये की 10 किश्तों पर कनेक्शन देने के साथ ही बीपीएल परिवारों को एक किट प्रदान की जायेगी।

विद्युत बिलों में संशोधन के लिए चलेगा अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल संशोधन अभियान 15 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जाएगा। अधिशासी अभियंता क्षेत्र में शिविर लगाकर बिल संशोधित करेंगे।

बिजली चोरी की सूचना देने पर पुरस्कार

बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बिजली चोरी की सूचना देने पर और उसकी शमन राशि 20 हजार या इससे अधिक होने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 प्रतिशत राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। इसके लिए 1912 एवं 18004001800 नंबर पर फोन किया जा सकता है।

पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 60 लाख अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की राशि को उनके विद्युत बिल में समायोजित किया जाएगा। अब तक उपभोक्ताओं से 5 के स्थान पर 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूली जा रही थी।

जनपदों का होगा रूपान्तरण

विगत कई वर्षों में देश का जी0डी0पी0 उच्च होने के बावजूद मानव विकास सूचकांक में देश 138 वें स्थान पर है। इस सूचकांक में देश को ऊंची पावदान पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा महत्वाकांक्षी जनपदों का रूपान्तरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आहूत बैठक में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जनपदों की शक्तियों, त्वरित सुधार हेतु कार्यों का चिन्हांकन, प्रगति का अनुश्रवण एवं तद्नुरूप जनपदों की रैकिंग पर केन्द्रित है। जनपदों को सर्वप्रथम राज्य के अन्दर सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में उभरना, प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहकारी संघवाद की भावना में प्रतिस्पर्धा करके और दूसरों से सीखकर देश में सर्वश्रेष्ठ बनने की परिकल्पना को महत्व दिया गया है।

विकास की दौड़ में पिछड़े जनपदों का होगा रूनपान्तरण

प्रदेश के आठ जनपद का हुआ चयन

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देशव्यापी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन जनपदों का त्वरित और प्रभावी रूपान्तरण करना है, जो किन्हीं कारणों से विकास की दौड़ में पिछड़ गये हैं। महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण हेतु नीति आयोग द्वारा पूरे देश से चयनित कुल 115 महत्वाकांक्षी जनपदों में प्रदेश के आठ जनपद–बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सि)ार्थनगर, सोनभद्र, चन्दौली, फतेहपुर तथा चित्रकूट शामिल हैं। इसके लिए जो व्यापक रूपरेखा तय की गई है उसका मुख्य आधार केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं में कन्वर्जन्स द्वारा उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। इसके लिए केन्द्रीय प्रभारी अधिकारियों, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों तथा सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक टीम के रूप में कार्य किया जाएगा। इसमें जन सहभागिता की भी बड़ी भूमिका होगी।

किसानों के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना

प्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना 2018 लागू की है। सरकार ने प्रदेश के किसानों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा अगले 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रदेश के ऐसे कृषक जिन्हे अल्पकालीन ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं किया गया था और जिन्होने दीर्घकालीन निवेश ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से प्राप्त किया था, को प्रदेश सरकार की सहमति से एक मुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जायेगा।

प्रदेश के किसानों के कल्याण को शीघ्र प्राथमिकता देते हुए एक मुश्त समाधान योजना 2018 लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 1997 तक वितरित ऋण प्रकरणों में कृषकों का समस्त ब्याज माफ किया जायेगा। इसी प्रकार 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 तक ऋण लेने वाले कृषकों से मूलधन के बराबर ब्याज लेकर अवशेष ब्याज की छूट दी जायेगी तथा 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच वितरित ऋणों में समझौता करने पर ब्याज में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

पिछड़े व अनुसूचित जाति को कम ब्याज पर मिलेगा ऋण

प्रदेश के पिछड़े व अनुसूचित जाति के किसानों के लिए रोजगारपरक योजनाओं हेतु कम ब्याज दर पर (6 प्रतिशत वार्षिक) ऋण उपलब्ध कराने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। भविष्य में प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कृषकों को भी कम ब्याज दर (6 प्रतिशत वार्षिक) ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि के लक्ष्य को सर्वोपरि रखते हुए कार्य किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक संख्या में किसान आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके।

2.63 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा फायदा

निवेश ऋण लेने वाले किसानों को होगा लाभ

योगी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई फसल ऋण मोचन योजना–2018 में निवेश ऋण को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः ऐसे कृषकों की संख्या काफी अधिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन निवेश ऋण प्राप्त किये हैं परन्तु कतिपय कारणों से अपना बकाया अदा नहीं कर पाये हैं। ऐसे किसानों के लिए ही एक मुश्त समाधान योजना 2018 लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 263510 कृषक आच्छादित होंगे, जिन पर कुल 2542.43 करोड़ रूपये बकाया हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ■

एक साल में बदली उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर

अपराधियों में जगा पुलिस का खौफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही सूबे की कानून व्यवस्था में सुधार का जो संकल्प लिया था, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। मात्र एक वर्ष के अल्प समय में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐसा सुधार आया है कि जो अपराधी पहले बेखौफ होकर घूमते थे, उनमें पुलिस का भय दिखने लगा है और वे अपराध की राह छोड़ रहे हैं। पहले जो उद्योगपति प्रदेश आने से भी कतराते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। आज आम जनता में यह विश्वास जगा है कि उनकी फरियाद सुनी जाएगी और कानून अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी का पूरी कुशलता से विर्वहन करेगा।

पुलिस के काम में किसी भी प्राकर का राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। अब पुलिस निर्भीक होकर अपना काम कर रही है, परिणाम स्वरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस वीक के अवसर पर यूपी-100 भवन में आयोजित समारोह में अच्छे कार्यों के लिए यूपी पुलिस की सराहना की और पुलिस अफसर किस प्रकार और बेहतर कार्य कर सकते हैं, इस बात पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, ताकि आम जन में पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर जो विश्वास जगा है, उसे और मजबूती मिल सके।

मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अपराधी चाहे कितना भी सशक्त व प्रभावशली क्यों न हो, उस पर शिकंजा कसने में पुलिस संकोच न करे। सरकार की नीति के कारण ही प्रदेश में लूट, डकैती और हत्या की घटनाओं में कमी आई है। बेहतर कानून व्यवस्था विकास की धुरी होती है।

साइबर क्राइम आधुनिक युग में कानून व्यवस्था के सम्मुख एक चुनौती बनकर उभरा है। इससे निपटने के लिए निरन्तर व प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

कार्यप्रणाली बदलने से मिलेगा जनसहयोग

वैसे तो आम जन में पुलिस को छवि पहले से बेहतर हुई है, फिर भी कई ऐसे बिन्दु हैं, जिन पर प्रदेश के पुलिस बलों को कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि वरिष्ठ पुलिस अफसर बेहतर कार्य और अच्छे व्यवहार से अपनी छवि सुधार सकते हैं। यदि पुलिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ करेगी तो उसे आम जनता का भपूर सहयोग मिलेगा और अप्रत्याशित घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। जब आम जनता को लगेगा कि पुलिस उसकी मित्र है, तब वह और अधिक मजबूती के साथ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और एक भयमुक्त समाज के निर्माण की मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर सकेगी।

सुरक्षा का तात्पर्य इस बात से है कि रात में अकेली महिला सार्वजनिक स्थान से सकुशल अपने घर पहुंच जाए। ऐसा जिस दिन होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे देश में अनुकरणीय हो जाएगी।

बुन्देलखण्ड में नहीं होगी पानी की कमी

बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसें पानी की कमी जैसी समस्या से निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है, परन्तु आम जन की पीड़ा समडने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की कमी किसी भी हाल में न हो। किसी इन्सान, पशु–पक्षी इत्यादि को पेयजल के संकट का सामना न करना पड़े। इसके लिए सारी तैयारियां समयबद्ध ढंग से कर ली जाएं।

समस्याओं के निस्तारण का होगा भौतिक सत्यापन

मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जायें और हर समस्या के निराकरण का भौतिक सत्यापन किया जाए। योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्यमंत्री जी स्वयं बुन्देलखण्ड के दौरे पर जाएंगे।

गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

बुन्देलखण्ड में पेयजल समस्या पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल निगम तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी बुन्देलखण्ड क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां कैम्प कर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

सभी जनपदों में पेयजल समस्या दूर करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट में पेयजल समस्या के समाधान के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायी जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर पेयजल समस्या के समाधान के लिए टीम बनायी जा रही हैं। अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में कन्ट्रोल रूप बनाए जाएंगे, जहां पर जिम्मेदार कर्मचारियों की उपस्थिति हागी। टैंकरों और पाइप से पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

तालाबों की खुदाई से दूर होगा पेयजल संकट

योगी जी ने सख्त निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या की शिकायत नहीं आनी चाहिए। तालाबों को प्राथमिकता के स्तर पर भरने और खुदवाने का कार्य भी किया जाएंगे। यह प्रयास भी किया जाएगा कि कम लागत में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक गांव तक पेयजल की व्यवस्था पहुंचे। योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग समयबद्ध ढंग से जनता के हित में किया जाए, ताकि बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके।

ई–टेण्डरिंग से बालू–मोरंग के अवध खनन पर रोक

खादानों की नीलामी से सरकार की आय 15 गुना बढ़ी

यूपी में बालू–मोरंग के खादानों पर ई–टेण्डरिंग के माध्यम से अवैध खनन पर अंकुश लगा है और इनकी कीमतों में भारी कमी आई है, जिससे आम जन को राहत मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा खादानों की नीलामी में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से मोरंग से होने वाली आय में लगभग 15 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में बालू–मोरंग और सभी उप खनिजों के खनन पट्टे ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया से जारी हुए हैं। अभी प्रदेश में मात्र 175 खादानें शुरू हुई हैं और बालू–मोरंग की दर घट गई हैं। सभी खादान शुरू होने के बाद कीमतों में और कमी आएगी।

गंगा के किनारों पर फैलेगी हरियाली

गंगा किनारे दोनों ओर एक किमी. में होगा पौधरोपण

बिजनौर से लेकर बलिया तक चलेगा अभियान

वन महोत्सव सहित विशेष तिथियों पर चलाया जायेगा विशेष अभियान

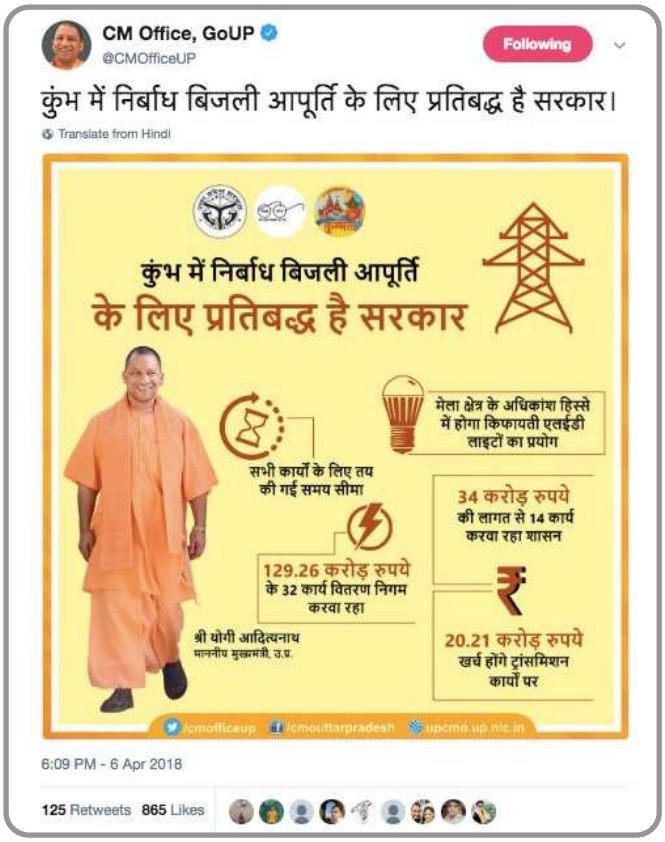

गंगा केवल एक नदी ही नहीं वरन् हमारी माता है, सभी भारतवासियों के लिए पूजनीया है और इसे निर्मल व स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है। गंगा की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संकल्पबद्ध हैं। गंगा की सफाई के साथ ही उसके किनारों को साफ–सुथरा और हरा–भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग द्वारा आयोजित 'हरीतिमा अभियान' समारोह में उपस्थित जनसमूह को 'एक व्यक्ति एक वृक्ष' और 'एक परिवार एक पंचवटी' के विकास का संकल्प दिलाया।

27 जिलों में चलेगा गंगा हरीतिमा अभियान

गंगा हरीतिमा अभियान गंगा नदी के किनारे बसे 27 जिलों के 130 ब्लॉकों में संचालित किया जायेगा। इस अभियान के लिए समस्त ग्राम पंचायतों में गंगा ग्राम सेवा समिततियां बनाई जाएंगी और गंगा के दोनों किनारों पर पौधरोपण का कार्य कराया जायेगा।

अभियान का प्रमुख उद्देश्य गंगा के किनारे फारेस्ट कवर बढ़ाना है। अभियान 16 सितम्बर 2018 तक चलेगा, जिसमें विशेष अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे। अभियान के अंतर्गत निजी भूमि पर पौधरोपण को प्रोत्साहित करने हेतु 'एक व्यक्ति–एक योजना' में सहयोग के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ■

अनूठा और भव्य होगा कुंभ–2019

मुख्यमंत्री जी ने संगम तट पर कुंभ के कार्यों हेतु 684 करोड़ की 151 परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए निर्देश दिए कि इन समस्त कार्यों को इसी वर्ष अक्टूबर तक पूरा करा लिया जाए। इससे पहले पांच सौ करोड़ की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया था, उन पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कुंभ में पर्यटक सड़क, हवाई और जल तीनों मार्गों से आएंगे, इसलिए ट्रेनों और बसों के साथ प्रयाग को हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कुंभ के आयोजन से पूर्व ही जल मार्ग से भी आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। कुंभ में लगभग 192 देशों के पर्यटकों के आने की आशा है। इसीलिए इससे जुड़े सभी आयोजनों पर मुख्यमंत्री जी स्वयं रूचि ले रहे हैं ताकि कुंभ–2019 के भव्य आयोजन में कोई कसर न रह जाए।

नशामुक्त होगा यूपी

हाईवे और सार्वजनिक स्थलों के निकट नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति के लिए नशामुक्ति है आवश्यक

नशमुक्ति अभियान के पालन से ही आगे बढ़ेगा देश और प्रदेश

आबादी के लिहाज से विश्व के केवल 3 देश उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। विशाल जनसंख्या प्रदेश की पूंजी है। वह स्वस्थ रहे इसकी श्रेष्ठता नशामुक्ति में है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर निकलें तो कोई भी काम मुश्किल या असंभव नहीं है। इस मुश्किल काम को जनसहभागिता के आधार पर किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने 'नशामुक्त उत्तर प्रदेश संकल्प समारोह' के अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में मादक पदार्थ का सेवन बढ़ रहा है जो पीड़ा देने की बात है और भावी समाज के लिये खतरे का निशान है। लखनऊ की धरती से स्वेच्छा और स्वयं प्रेरणा से उत्तर प्रदेश नशामुक्ति का संग्राम शुरू हो रहा है। आज ली गई शपथ को सिद्धि तक ले जाकर नशामुक्ति को सफल बनाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिये शार्टकट नहीं बल्कि पुरूषार्थ और परिश्रम की आवश्यकता है। किसी भी संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिये सात्विकता चाहिये। प्रधानमंत्री ने संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया है। आमजन में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है कि राजमार्गो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। जनसहभागिता से संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिये सरकार हर संभव प्रयास करेगी।

यूपी में निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकरण शुरू

Niveshmitra.up.nic.in है यूआएल

ऑनलाइन ही करना होगा पंजीकरण शुल्क का भुगतान

संबंधित विभागों को शासन द्वारा निर्धारित समय पर ही उपलब्ध कराना होगा प्रमाण पत्र

नया उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों, अनुमोदनों और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित समय पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

टर्न ओवर की बाध्यता समाप्त

इस पोर्टल पर कोई भी उद्यमी, उसका टर्नओवर चाहे जितना हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सरकार ने छोटे उद्यमियों को सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से टर्नओवर की बआध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले यह सीमा 50 करोड़ थी।

मिल गया यूआरएल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इन्वेस्टर्स समिट में निवेश पोर्टल लांच किया था। इसका यूआरएल रजिस्ट्रेशन के लिए लिए सार्वजनिक होते ही इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू साइन करने वाले उद्यमियों के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।

ऐसे काम करेगा पोर्टल

पोर्टल की निगरानी केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अफसर करेंगे। प्रमाण पत्र संबंधी कार्य कराने का उत्तरदायित्व प्रादेशिक उद्योग बंधु का होगा। उद्यमियों को निवेश मित्र के वेब पेज पर एक कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरना होगा, जो उद्योग बंधु के पास खुलेगा। फार्म स्वीकृत होने के बाद उद्यमी के वेब पेज पर स्वतः ही सभी विभागों के वेब पेज खुलेंगे और संबंधित फार्म भरने होंगे।

10 अप्रैल 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

दुधवा बांघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन से ईको टूरिज्म को बढ़ावा

योगी सरकार ने दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। फाउंडेशन गठित होन से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। फाउंडेशन की आय पर्यटकों के प्रवेश शुल्क, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के सहयोग से की जाएगी। इसके अन्तर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर कार्य करने वाले व्यक्ति तथा एनजीओ अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

फाउंडेशन की निगरानी एक 12 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं वन मंत्री करेंगे। फाउंडेशन के दैनिक कार्यो पर नजर रखने हेतु वन विभाग के फील्ड आफिसर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित होगी।

इस फाउंडेशन के गठन से दुधवा के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों को रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने प्रदेश में दो अन्य बाघ संरक्षण फाउंडेशन पर विचार करने का निर्णय लिया है।

कोरिया गणराज्य एवं उत्तर प्रदेश के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरिया गणराज्य के राजदूत शिन बान्गकिल जी से भेंट करते हुए

जाइंट और मंडलीय कमांडेंट का एक-एक पद बढ़ेगा होमगार्ड विभाग में

बलिया में बनेगा 100 व्यक्तियों की क्षमता का बहुउद्देशीय सभागार

फिर से चलेगी पीलीभीत की मझोला सहकारी चीनी मिल

केन्द्र सरकार के साथ 15 वर्ष के लिए बढ़ा त्रिपक्षीय करार

दो वर्ष से पहले दूसरे निगम में नहीं बनेंगे निदेशक

यूपीपीसीएल की पांच वितरण कंपनियों के अतिरिक्त पद्रेश में कई ऊर्जा निगम हैं। अक्सर दूसरे निगमों में जाने के कारण निदेशक प्रतिबद्धता के साथ अपना कार्य नहीं कर पाते। अतः ऊर्जा विभ्राग में स्थायित्व को बढ़ावा देने और कामकाज को सुचारू रूप से गतिमान रखने के उद्देश्य से कैबिनेट ने निर्धय लिया है कि अब दो वर्ष से पूर्व किसी भी निगम का निदेशक दूसरे निगम का निदेशक नहीं बन सकेगा परन्तु निदेशक संबंधित निगम का प्रबंध निदेशक बन सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से निगम व कंपनियों में कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी